

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 78/2014

दायर तारीख : 10.04.14

1. मोहन पुत्र स्व० रेखाराम जाति कुम्हार नि० खण्डेल तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०  
— वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र स्व० गणेश
2. दिनेश पुत्र स्व० गणेश
3. सुन्दरदेवी पत्नि स्व० मानाराम
4. मंगलाराम पुत्र स्व० मानाराम
5. बोदूराम पुत्र स्व० मानाराम
6. श्योजीराम पुत्र स्व० मानाराम
7. नन्दाराम पुत्र स्व० मानाराम
8. लालाराम पुत्र स्व० मानाराम
9. लाडादेवी पुत्री स्व० मानाराम
10. गीधा पुत्र स्व० रेखाराम
11. छोटू पुत्र स्व० पूराराम
12. दाखादेवी पत्नि छोटूराम

- समस्त जाति कुम्हार नि० खण्डेल तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०
13. एस०बी०बी०जे० शाखा फुलेरा जरिये मैनेजर
  14. तहसीलदार फुलेरा तह० फुलेरा जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थित : — श्री योगेश कुमार शुक्ला अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी  
श्री लालचन्द कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थीगण सं० 1 व 2  
पैरोकार सरकार

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :- 22/8-17

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने प्रा०पत्र आर्डर 7 नियम 1 जा०दी० पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद विभाजन का प्रस्तुत करने के पश्चात् वादी को जिस नामान्तकरण सं० 175 के द्वारा खातेदारी दी गई थी उसको न्यायालय द्वारा अधील उनवानी कैलाश बनाम ग्राम पंचायत को स्वीकार कर दिनांक 20.07.17 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण सं० 175 निरस्त कर रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ कर दिया है। इस कारण अन्य वादी उक्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार नहीं रहा है जिसको उक्त आराजी के विभाजन का वाद संधारण करने का कोई कानूनी अधिकार

उप खण्ड अधिकारी  
सांभर लेक

प्राप्त नहीं है तथा इस वाद का वाद कारण समाप्त हो चुका है इस कारण वदी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

3. अप्रार्थी/वादी का जवाब रहा कि उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 20.03.18 में निगरानी उनवानी मोहन उर्फ मूना बनाम ग्राम पंचायत खण्डेल निगरानी सं० 1925/2018 पेश कर दी है। जिसमें कानूनी बिन्दू निहित होने के कारण स्थगन आदेश पारित किया है। जिसका नोट तहसील व राजस्व में अंकित किया जा चुका है व पत्रावली को तलब की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चैलेन्ज दिया जा चुका है। जो मामला व कानूनी बिन्दू माननीय राजस्व मण्डल के सामने विचाराधीन है। प्रतिवादी का वादकारण निरन्तर जारी है वाद चलाने संधारण करने का पूरा कानूनी अधिकार प्रतिवादी को है मौके पर आज भी 1/3 हिस्सा भूमि पर जो विरासत में मोहन को प्राप्त हुआ है प्रतिवादी मोहन को उस पर भौतिक रूप से काबिज है। प्रार्थी वादी का प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 सव्य खारिज किये जाने योग्य है। धारा 12 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम इस सम्बन्ध में विधि का दत्तक पुत्र के अधिकारों के सम्बन्ध में सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति में सम्पत्ति में निहित अधिकार है तो दत्तक चले जाने के पश्चात् भी यह अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। इस तथ्य माननीय सिविल न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक द्वारा कैलाश बनाम मोहन के घोषण स्थाई निषेधाज्ञा के वाद व टी०आई० प्रा०पत्र में निर्धारित करते हुए दिनांक 11.07.13 को कैलाश बनाम मोहन का प्रा०पत्र खारिज फरमा दिया गया व इसके पश्चात् वादी ने स्वयं का केस खारिज करवा लिया यहा वादी कैलाश ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को छिपाकर प्रा०पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा पेश प्रा०पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा०दी० का खारिज किये जाने योग्य है।

4. वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने अपने प्रा०पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2071-74 पेश की है तथा वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा०पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रेवन्यू बोर्ड क स्थगन प्रति, मिल तलबी फोटो प्रति, सिविल कोर्ट सांभरलेक की खारिज कैलाश बनाम मोहन की प्रतिया पेश की है।

5. वहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वकूलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी वहस में कथन किया कि वादी ने उक्त वाद विभाजन का प्रस्तुत करने के पश्चात् वादी को जिस नामान्तकरण सं० 175 के द्वारा खातेदारी दी गई थी उसको न्यायालय द्वारा अपील उनवानी कैलाश बनाम ग्राम पंचायत को स्वीकार कर दिनांक 20.07.17 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण सं० 175 निरस्त कर रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ कर दिया है। इस कारण अन्य वादी उक्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार नहीं रहा है जिसको उक्त आराजी के विभाजन का वाद संधारण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा इस वाद का वाद कारण समाप्त हो चुका है

उप खण्ड अधिकारी  
सांभर लोक

इस कारण आदी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से अपनी बहस में कथन किया कि उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 20.03.18 में निगरानी उनवानी मोहन उर्फ मूना बनाम ग्राम पंचायत खण्डेल निगरानी सं० 1925/2018 पेश कर दी है। जिसमें कानूनी बिन्दू निहित होने के कारण स्थगन आदेश पारित किया है। जिसका नोट तहसील व राजस्व में अंकित किया जा चुका है व पत्रावली को तलब की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चैलेन्ज दिया जा चुका है। जो मामला व कानूनी बिन्दू माननीय राजस्व मण्डल के सामने विचाराधीन है। प्रतिवादी का वादकारण निरन्तर जारी है व वाद चलाने संधारण करने का पूरा कानूनी अधिकार प्रतिवादी को है मौके पर आज भी 1/3 हिस्सा भूमि पर जो विरासत में मोहन को प्राप्त हुआ है प्रतिवादी मोहन को उस पर भौतिक रूप से काबिज है। प्रार्थी वादी का प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

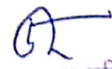
6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। वादी को जिस नामान्तकरण सं० 175 के द्वारा खातेदारी दी गई थी उसको न्यायालय द्वारा अपील उनवानी कैलाश बनाम ग्राम पंचायत को स्वीकार कर दिनांक 20.07.17 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण सं० 175 निरस्त कर रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ कर दिया है। इस कारण अन्य वादी उक्त आराजी का रिकोर्ड खातेदार नहीं रहा है इसलिए उक्त वाद आर्डर 7 रूल 11 जा०दी० के तहत खारिज किया जाता है। इसलिए वाद आर्डर 7 नियम 11 जा०दी० के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा०पत्र आर्डर 7 नियम 11 जा०दी० का स्वीकार किया जाकर वादी/अप्रार्थी का वाद आर्डर 7 नियम 11 जा०दी० के तहत खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमा-ए-आम में दिनांक 22-8-19 को सुनाया गया।



  
(मुकेश कुमार मूंड)  
उपखण्ड अधिकारी  
सांभर लेक